



सबलं मनः हृदयं च
तिलम् संघ
TILAM SANGH

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.
(तिलम् संघ) कोटा पश्चिमी ना

रावतभाटा रोड, पी.ओ. इन्जिनियरिंग कॉलेज, कोटा T-324010 (राज.)

☎: EPBX: 2470083, 2471464, GM: 2471183, Fax: (0744) 2471268

E-Mail - tilamsangh@gmail.com

यांत्रिक इलैक्ट्रीकल उपकरण संचालन एवं रखरखाव कार्य

निविदा प्रपत्र

1.	निविदा वर्ष	2020-21
2.	निविदा प्रपत्र शुल्क	रु. 500/-
3.	घरहे र राशि	रु. 10000/-
4.	निविदित कार्य का वार्षिक अनुमानित मुल्य	रु. 5.00 लाख
5.	निविदा प्रपत्र विवरण	
	पृ.सं. क्रमांक	विवरण
	पृष्ठ 1	निविदा प्रार्थना पत्र
	पृष्ठ 2	निविदा प्रपत्र
	पृष्ठ 3	निविदा प्रपत्र अ (टेक्नीकल बिड)
	पृष्ठ 4 से 6	निविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तें
	पृष्ठ 7 से 8	निविदा प्रपत्र ब (वित्तीय बिड)
	पृष्ठ 9	प्रारूप-इकरारनामा
	पृष्ठ 10 से 14	राजस्थान लक्रे उपापन में पारदर्शित T अधिनियम 2012 अन्तर्गत परिशिष्ट-A, B, C, D & Form No-1

निविदा प्रार्थना - पत्र

सेवामें,
महा प्रबन्धक,
तिलम् संघ कोटा।

महोदय,

मैं/हम कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैंने/हमने इस निविदा हेतु कोटा पश्चिमी ना तिलम् संघ द्वारा जारी किया गया निविदा प्रपत्र, दिशा-निर्देशों एवं शर्तों (ट्रम्स एण्ड कण्डीशन) को पढ़ व समझ लिया/लिये हैं। मैं/हम सभी दस्तावेजों की शर्तों को मानने के लिये बाध्य हूँ/हैं। मैं/हम तिलम् संघ के उक्त निविदा कार्य हेतु तिलम् संघ कोटा के लिये विभिन्न कार्यों की दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक :

निविदादाता का नाम

स्थान :

पता :

मोबाईल नं.:

पृष्ठ संख्या-01

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.(तिलम् संघ)काटे ।

यांत्रिक इलैक्ट्रीकल उपकरण संचालन एवं रखरखाव कार्य

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तारीख	17.07.2020	को 5.00 बजे तक
निविदा स्वीकार की अंतिम तारीख	18.07.2020	को दोपे हर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक, समय	18.07.2020	को दोपहर 3.00 बजे

निविदा फार्म का मूल्य नगद राशि रूपये 500/- रसीद संख्यादिनांक
से जमा कराया गया तथा निविदा प्रपत्र भाग 'अ' तथा 'ब' सम्भलाया गया।

निविदा फार्म जारीकर्ता
वास्ते तिलम् संघ । राजस्थान ,
कोटा प्रोजेक्ट

- 1 निविदादाता का नाम व व्यवसाय
का पूर्ण पता , फोन नम्बर आदि।
- 2 फर्म के अधिकृत व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता
- 3 धरोहर राशि रूपये 10000/- का बैंक ड्राफ्ट नम्बरदिनांक
सलग्न कर दिया गया है।

नोट: निविदा प्रपत्र का भाग 'अ' एवं 'ब' अलग अलग लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें साथ ही लिफाफे पर सम्बन्धित निविदा का कार्य विवरण अंकित करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.(तिलम् संघ)काटे 1
तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग 'अ'
प्रश्नावली

1. निविदादाता/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :
2. निविदादाता/फर्म का अनुभव विवरण :

सम्बोधन संस्थान का कार्य जो किया गया नाम एवं पता	श्रमिकों की संख्या जो काम में ली गई	अवधि से तक
--	-------------------------------------	------------

3. निविदादाता के बैंक के नाम जो कि फर्म की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करता है (बैंक स्टेटेमेंट संलग्न करें) :
4. निविदादाता द्वारा लिये गये लैब र लाइसेंस का विवरण (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें) :
5. निविदादाता का भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन एवं कोड संख्या का विवरण :
6. निविदादाता का आयकर स्थाई लेखा संख्या (पैन) (स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :
7. निविदादाता का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं. रजिस्ट्रेशन की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें :
8. निविदादाता फर्म द्वारा गत वर्षों में सफलतापूर्वक सम्पादित किये गये यांत्रिक, इलैक्ट्रीकल उपकरण संचालन एवं रखरखाव कार्यों का पूर्ण विवरण, न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें :

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग 'अ' में वर्णित सभी बिन्दुओं पर चाही गई सूचना पूर्ण कर ली गई है तथा तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें पढ़ ली गई हैं, समझ ली गई हैं तथा स्वीकार हैं। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा प्रपत्र 'ब' खले जावेगी।

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.(तिलम् संघ)कोटा

निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं निर्देश

निविदा भरते समय शर्तों का ध्यान पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए। इस अनुबन्ध में राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) कोटा परियोजना को 'परियोजना' सम्बोधित किया जावेगा एवं निविदाकार को 'निविदादाता' सम्बोधित किया जावेगा।

1. निविदा प्रपत्र पार्टी को अपने स्वयं के नाम एवं पते से खरीदना आवश्यक है क्योंकि यह प्रपत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. राजस्थान पब्लिक प्रोक्जियरमेंट में पारदर्शिता एक्ट – 2012 व इसके नियम 2013 इस निविदा पर लागू होंगे।
3. निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तों के अनुसार देखभाल कर भरें क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आपकी निविदा निरस्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र का भाग 'अ' एवं 'ब' अलग अलग लिफाफे में प्रस्तुत किये जावें साथ ही लिफाफे पर सम्बन्धित निविदा का कार्य विवरण अंकित करें। तकनीकी निविदा 'अ' में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा प्रपत्र 'ब' खोला जावेगा।
4. निविदा प्रपत्र स्वच्छ रूप से बिना कांट छंट के भरा होना चाहिये। किसी भी प्रकार की कटिंग (अवे रराइटिंग) पर पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
5. निविदा प्रपत्र बन्द लिफाफे में व्यक्तिगत तौर पर निश्चित समयानुसार निविदा पात्र में डालना होगा अथवा प्रोक्जियरमेंट के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी निविदायें भेजी जा सकती है। परन्तु किसी प्रकार के विलम्ब के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. निविदा फार्म के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो "राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. कोटा" के नाम हो, संलग्न करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। चेक द्वारा धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. निविदादाता के पास स्वयं का भविष्य निधि कोड़ा होना आवश्यक है। ठेकेदार को भविष्य निधि नियमानुसार लेखा जोखा तैयार करने एवं निरीक्षण द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर रिकार्ड प्रस्तुत कर निरीक्षण करवाने आदि समस्त जिम्मेदारी पूर्ण करनी होगी। यदि ठेकेदार की लापरवाही से श्रमिकों के फार्म नहीं भरने अथवा भविष्य निधि अंशदान की कटौती नहीं होने के कारण किसी श्रमिक को भविष्य निधि का लाभ उठाने में परेशानी होती है तो समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेकेदार के देय बिलों से समस्त राशि वसूल की जावेगी।
8. निविदादाता के पास श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लाईसेन्स होने चाहिए इस सन्दर्भ में लाईसेन्स की फोटोकॉपी संलग्न करें।
9. प्रत्येक माह के कार्य के बिलों का भुगतान कार्यप्रभारी एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने पर फौकट्री एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ति करने पर दूसरे माह की 15 तारीख तक किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा बिल भुगतान के विपरीत अग्रिम चाहने पर मजदूरों को वेतन भुगतान करने हेतु बिल राशि का 75 प्रतिशत बतौर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा।
10. धरोहर राशि एवं अमानत राशि पर प्रोजेक्ट द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि सुरक्षा राशि में परिवर्तित समझी जावेगी एवं शेष असफल निविदादाताओं को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त धरोहर राशि बैंक द्वारा वापिस लौटा दी जावेगी।

11. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न प्रोफार्मा में इकरारनामा करना वांछनीय है, जिसमें सभी शर्तें निहित होंगी एवं जो दाने ों पक्षों के लिए बंधनकारी होगी।
12. दरों की यूनिट का किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तथा दरों का इंड्राज अंकों व शब्दों में किया जाना चाहिए। इस निविदा में वर्णित मात्रा/संख्या को कम/ज्यादा करने का अधिकार परियाजे ना को रहेगा तथा इस स्थिति में सामान्यतः निविदादाता को दरें कम/ज्यादा करने का अधिकार नहीं होगा।
13. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में दी गयी समस्त शर्तें मान्य होगी तथा निविदादाता द्वारा रखी गई/जोड़ी गई कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
14. कार्य आवंटन न हने पर धराहर राशि को सुरक्षा राशि में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित कार्य के वार्षिक अनुमानित कीमत की 5% राशि कार्य निष्पादन सिक्वोरिटी के रूप में कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् 10 दिवस में जमा करानी आवश्यक होगी जिसे कार्य आदेश की अवधि पश्चात् कार्यसंतोष प्रद पाये जाने पर एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लौटा दी जावेगी। एसे ही जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
15. निविदादाता को कार्य आदेश की समस्त शर्तों की पूर्ति कर निश्चित समय एवं दिनांक को कार्य प्रारम्भ करना हगे। अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
16. निविदादाता द्वारा बिल तीन प्रतियों में सम्बन्धित अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
17. निविदादाता को स्वयं द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मान्य बीमा पॉलिसी लेना आवश्यक है, जिसका भुगतान परियाजे ना द्वारा नहीं किया जावेगा।
18. कार्य करते समय किसी भी श्रमिक को दुर्घटना से होने वाले नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
19. न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करते पाये जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार के आदेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान बैंक/हस्तान्तरण के माध्यम से किया जाना होगा।
20. निविदादाता को स्वयं के श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान वेतन अदायगी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व करना आवश्यक है। इसके लिए श्रमिकों का उपस्थिति रिकार्ड तथा अग्रिम भुगतान रजिस्टर आदि उपलब्ध रखना होगा। निश्चित तिथि पर भुगतान न करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
21. श्रमिकों द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, कार्य का बहिष्कार करने या अन्य विवाद खड़ा करने पर प्रोजेक्ट को होने वाले नुकसान के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. निविदादाता का कार्य संतोषप्रद होने अथवा आवश्यकतानुसार अनुबन्धक शर्तों पर कार्य आदेश की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
23. ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर परियाजे ना प्रबन्धन द्वारा 24 घण्टे पूर्व नोटिस देकर आदेश रद्द करने तथा ठेकेदार की जमा स्फुक्षा राशि जब्त करने का अधिकार परियाजे ना महापत्र न्धक को हगे।।
24. सरकार के नियमों के अनुसार ठेकेदार के देय बिलों से आयकर या अन्य वैधानिक कटौती की जावेगी।
25. सर्विस टैक्स लागू होने पर निविदादाता द्वारा सर्विस टैक्स जमा कराया जाता है, तो बिल में प्रस्तुत करने पर तिलम् संघ द्वारा नियमानुसार पुर्नभरण किया जायेगा।।

26. सम्बन्धित ठेकेदार परियाजे ना की ख्याति व उसके व्यावसायिक हितों का उसी निष्ठा से ध्यान रखेगा । जेसा की वह अपनी ख्याति व हितों की रखता है । जो जानकारी गोपनीय हो उसे उजागर नहीं करेगा और ना ही ऐसा कार्य करेगा जिससे परियाजे ना के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े ।
27. कार्य से सम्बन्धित समस्त विवाद के निपटारे के लिए कोटा शहर न्यायिक क्षेत्र होगा । निविदा की शर्तों में अथवा कार्य सम्पादित करते हुए किसी फ़ार के विवाद के हल हेतु संधि के प्लान्थ संचालक का निर्णय सर्वोपरि हगे । और दने ि पक्षों को मान्य होगा ।

महाप्रबन्धक

हस्ताक्षर
निविदादाता

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.(तिलम् संघ)काटे 1
वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग "ब"

तिलम संघ कोटा परियोजना में यांत्रिक, इलैक्ट्रिकल, उपकरण संचालन व रखरखाव कार्य विवरण

1. विद्युत रखा रखाव एवं यांत्रिक उपकरण संचालन से सम्बन्धित :-

पैकिंग प्लान्ट , ग्रेडिंग , बल्क अनलोडिंग , ऑफिस, कॉलाने ी , पस्थिाजे ना परिसर में इलैक्ट्रीकल से सम्बन्धित रखरखाव कार्य जैसे :-ब्रेक डाउन अटेण्ड करना , लाईटिंग व्यवस्था आदि विद्युत सम्बन्धित समस्त कार्य।

Note:

1 उक्त कार्य के लिये प्रत्येक शिफ्ट में एक इलैक् ट्रीशियन व जनरल शिफ्ट में एक हेल्पर उपलब्ध कराने होंगे, जो कि विद्युत विभाग की आवश्यकतानुरूप हों। इलैक् ट्रीशियन की आई टी आई सर्टिफिकेट्स/वायरमैन सर्टिफिकेट की प्रति (प्रमाणित) उपलब्ध करानी होगी।

2 पम्प हाउस से सम्बन्धित विभिन्न कार्य तथा पम्पों का संचालन/वाल्व खोलना/बन्द करना आदि कार्य भी करने होंगे।

3 परियोजना प्रशासनिक भवन में लगे हुए इनवर्टरों की बैटरी का मेन्टीनेन्स/रखरखाव करना, अतः 15-15 दिन में (माह में दो बार) बैटरी का पानी इत्यादि चेक कर सहायक प्रबन्धक इलैक्ट्रीकल को सूचित करना।

4 टूल्स व टेकल्स आवश्यकतानुसार परियोजना द्वारा लोन पर उपलब्ध करवाये जावेंगे। जिन्हें कार्य समाप्ति पर पुनः परियोजना में जमा करवाना होगा।

5 स्पेयर पार्ट्स एवं कंज्यूमेबल आइटमस परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।

शर्तें :-

1. किसी भी कारणवश ठेकेदार के कर्मचारी की लापरवाही व गैर जिम्मेदारी से परियोजना को हानि होती है तो समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
2. बिना किसी कारणवश विद्युत दोष निवारण में अनावश्यक समय लगता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
3. पावर फेक्टर को मेन्टेन करना होगा ताकि विद्युत विभाग द्वारा पेनल्टी न लगे यदि कोई पेनल्टी लगती है तो उसकी कटौति ठेकेदार को देय बिलों से की जावेगी। इसमें कोई परेशानी हो तो तुरन्त सहायक प्रबन्धक (विद्युत) अथवा शिफ्ट इंचार्ज को सूचित करना होगा।
4. एस. ई. पी. में अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं अतः वहां कार्य अति कुशलता से करना होगा एवं इस स्थान पर कार्य में विशेष ध्यान रखना होगा।

5. परियोजना में रूडे लाईटें ठीक करते समय हमारे केम्पस से बिजली विभाग की दो हाईटरें इन लाईने गुजर रही है इनसे दुर्घटना ना हो, ध्यान रखना होगा।
6. देय बिलों से नियमानुसार टीडीएस इत्यादि विधिक कटौतियां की जावेंगी।
7. सोलवेन्ट/रिफायनरी/ऑयल मिल चलने की स्थिति में दरें नेगोशियेट कर ली जावेंगी।
8. निर्धारित समय में कार्य न करवाये जाने की स्थिति में ठेकेदार की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कार्य करवा लिया जावेगा।
9. किसी भी शिफ्ट में इलैक्ट्रीशियन/हैल्पर उपलब्ध न कराने की स्थिति में 250/- रु. प्रति कर्मचारी हर्जाना वसूल किया जावेगा।

—: घोषणा :—

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें सवीकार हैं।

—: दर :—

मैं/हम कम संख्या 1 पर अंकित कार्य की कुल भुगतान दर (समस्त खर्चों सहित) रुपयेअक्षरे रुपयेप्रतिमाह पर कार्य करने को तैयार हैं।

निविदादाता हस्ताक्षर

500 रु के नॉन ज्यूडिशियल
स्टाम्प पेपर पर देना है।

— इकरारनामा —

यह इकरारनामा आज दिनांक को राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि.(तिलम् संघ 1), कोटा जिसे आगे चलकर परियोजना के नाम से सम्बोधित किया गया है। तथा द्वारा जिसे आगे चलकर निविदादाता के नाम से सम्बोधित किया गया है के बीच निष्पादित किया जाता है। परियोजना द्वारा निविदादाता को कार्यादेश व अन्य निर्देशों के अनुसार तिलम् संघ कोटा परियोजना में कार्य सौंपा जाता है तथा इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पादन एवं संचालन हेतु परियोजना एवं निविदादाता के बीच में यह इकरारनामा किया जाता है :-

1. निविदादाता को परियाजे ना में निर्देशित संख्या में श्रमिक उपलब्ध करना स्वीकार्य है, दरें कार्य आदेश के अनुसार होगी व इस इकरारनामें के तहत आवश्यकतानुसार कार्य आदेश/निर्देश दिये जावेंगे। शर्तें कार्य आदेश 1, इकरारनामें व सुरक्षा राशि व समय समय पर दिये निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।
2. निविदादाता परियाजे ना की ख्याति एवं उसके व्यावसायिक हितों को उसी निष्ठा से ध्यान रखेगा जैसे वह अपनी ख्याति और हितों को रखता है। जो जानकारी गापे नीय हो उसे उजागर नहीं करेगा, और ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे परियोजना के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
3. निविदादाता द्वारा वांछित मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने एवं परियाजे ना के हितों एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या निविदा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में बिना फ्लू स्क्रू ना के कार्य आदेश निरस्त कर सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। निविदा/कार्य समयावधि का शेष कार्य निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य व्यवस्था से सम्पादित करवाया जा सकता है। निविदादाता द्वारा परियोजना को पहुंचायी किसी प्रकार की हानि या परियोजना द्वारा लगायी शास्ति की वसूलि निविदादाता को देय भुगतान में से की जा सकती है अथवा अलग से वसूलि जा सकती है।
4. इस इकरारनामें की शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो परियोजना निविदा प्रपत्र एवं कार्य आदेश 1 में दी है भी यथावत लागू रहेंगी। साथ ही समय समय पर आवश्यकतानुसार दिये निर्देशों की पालना करनी होगी एवं इस इकरारनामें / अनुबन्ध का हिस्सा रहेंगे। इस इकरारनामें की शर्तों के सम्बन्ध में या किसी प्रकार के अन्य विवाद की स्थिति में तिलम संघ 1 के प्रबन्ध संचालक महोदय का निर्णय सर्वोपरि एवं अंतिम हूँगे। और दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

यह इकरारनामा परियाजे ना महाप्रबन्धक श्री व निविदादाता श्री के द्वारा आज दिनांकको आपसी सहमति से एवं स्क्रू बूझ से लिया गया है। जो कि वक्त बचे वक्त काम आवे।

कोटा (राज.)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

निविदादाता मोहर

परियोजना अधिकारी मोहर

गवाह : 1

2.

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित 1 अधिनियम 2012 अन्तर्गत Annexure A :
Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i, A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participates as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित I अधिनियम 2012 अन्तर्गत **Annexure B :**
Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
..... in response to their Notice Bids No..... Dated I/we hereby de-
clare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत Annexure C :

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Managing Director, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Marg, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Ex-Officio Administrator, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Marg, Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

.....
(Supported by an affidavit)

7. Prayer :
.....

Place

Date

Appellant's Signature

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत **Annexure D :**
Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.